भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

19.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3173 का उत्तर

महाकुंभ 2025 के लिए विशेष रेलगाड़ियां

3173. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाकुंभ 2025 के लिए भारतीय रेल द्वारा कुल कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) इन विशेष रेलगाड़ियों की जोन-वार और मार्ग-वार सूची क्या है;

(ग) महाकुंभ अवधि के दौरान भारतीय रेल के माध्यम से प्रयागराज आने-जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस अवधि के दौरान टिकटों की बिक्री से भारतीय रेल को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या इस महाकुंभ के दौरान हाल ही के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी दुर्घटना के अलावा देश के किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है; और

(च) उक्त भगदड़ों में कितनी मौतें हुई हैं और पीड़ितों के परिवारों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) महाकुंभ-2025 के दौरान यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रेल ने 17,300 से ज़्यादा गाड़ियां चलाईं, जिनमें 7484 स्पेशल रेल सेवाएं शामिल थीं। इन स्पेशल रेल सेवाओं में 996 लंबी दूरी की गाड़ियां शामिल हैं। कुंभ 2019 के दौरान, 8394 गाड़ियां चलाई गईं थी जिनमें 694 स्पेशल रेल सेवाएं शामिल थीं।

इन सभी उपायों से लगभग 4.24 करोड़ यात्रियों को सेवा मिली। भारतीय रेल स्टेशन-वार, गाड़ी-वार (स्पेशल रेल सेवाओं सहित) राजस्व के आंकड़े नहीं रखती है।

(ङ) और (च) महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के अलावा देश में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है। बहरहाल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कुल 18 व्यक्ति हताहत हुए।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-ए (धारा 123 के साथ पठित) के तहत परिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट के लिए रेलवे मुआवजा देता है, जिसका निर्णय रेल दावा न्यायाधिकरण द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए दावे के आवेदन के आधार पर किया जाता है और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामलों का निपटारा करता है। जब माननीय रेल दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है और रेलवे उस निर्णय को लागू करने का निर्णय लेता है, तो रेल प्रशासन मुआवजा देता है।

****